>

Title: Combined discussion on the Budget for the State of Jharkhand for 2013-14; Demands for Grants in respect of Budget for 2013-14; Supplementary Demands for Grants for 2012-13 (Discussion concluded).

MADAM SPEAKER: Motions moved:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 2014, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 4, 6 to 12, 15 to 27, 29 to 33 and 35 to 60."

> "That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand, to defray the charges during the year ending the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3, 10, 16, 18 to 20, 22, 23, 25 26, 33, 36, 40, 41, 43 to 45, 48 to 51, 53, 54, 56 and 58."

Now, Shri Nishikant Dubey to speak.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया जी, मैं थोड़ा ही बोलूंगा, लेकिन साढ़े तीन करोड़ जनता का सवाल है और माननीय यशवंत जी और नामधारी जी ने जो कहा वह आपने सुना। यदि विधान सभा नहीं चल रही है तो वहां की जनता की आवाज को आपको सुनना चाहिए। अभी आपने कहा कि वोट ऑन एकाउंट नहीं लेना है, इलैक्टिड गवर्नमेंट के लिए हमने खुली छूट दी हुई है। जो कल होम मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, कितना कंफ्यूज़न कांग्रेस में है। मैं आपके बजट भाषण पर बाद में जाऊंगा, उन्होंने कहा कि 28 लोगों ने कहा कि यह विधान सभा भंग हो जानी चाहिए। अब ये 11 आदमी डॉ. अजय कुमार जी की पार्टी के थे, उन्होंने कहा कि ये 11 आदमी भी चुनाव के पक्ष में हैं और इसके बाद कहा कि दो छोटी-छोटी पार्टियां थीं जिनके एक-एक एमएलए हैं, उन्होंने भी कहा कि यह विधान सभा भंग हो जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, 82 सदस्यों की सदन में खुद गवर्नर की रिपोर्ट कह रही है और होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कल इसकी चर्चा की कि 41 लोग कहते हैं कि चुनाव कराइये, तो क्या ऐसी मजबूरी है कि एसेम्बली को डिजोल्व नहीं कर रहे हैं, होर्स-ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यदि आपमें संविधान के प्रति आस्था है तो आप सरकार बनाइये, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस पिछले वर्ष 2009 में चुनाव साथ लड़ चुकी हैं। आपके एक एमपी यहां जीतकर आये हैं। आप मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बना चुके हैं, एनओ सिक्का, हरिनारायण राय आदि सबके साथ आप सरकार बनाइये और यदि नहीं बना सकते हैं तो आप असेम्बली को डिजोल्व कीजिए। वोट ऑन एकाउंट आप लेते तो आपके लिए सुविधा होती। क्या स्थिति आपने झारखंड की कर दी है?

मैडम, मैं देवघर से हूं, द्वादश ज्योतिर्लिंग का एक लिंग है शक्तिपीठ है, पार्श्वनाथ हैं जहां तेइसवें तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया। महात्मा गांधी देवघर में अपना आश्रम खोलना चाहते थे, महर्षि अरविंद पांडिचेरी जाने से पहले देवघर में थे, विवेकानंद जी शिकागो जाने से पहले देवघर में थे, ईश्वरचंद विद्यासागर झारखंड में पैदा हुए। रवीन्द्र नाथ टैगोर अपना शांति-निकेतन वहां बनाना चाहते थे। हम लोग सिद्धु, कानू, बिरसा-मुंडा, तिलका-मांझी इस तरह की परम्परा के वाहक रहे हैं लेकिन आज झारखंड का यदि नाम आता है तो मधु-कोड़ा को लोग याद करते हैं, हरिनारायण राय को याद करते हैं, एनओ सिक्का को याद करते हैं, करप्शन को याद करते हैं। पूरा का पूरा झारखंड आपने बर्बाद कर रखा है। आपका कंफ्यूज़न इस पूरे बजट में है। आप कह रहे हैं कि दो बार आपने राष्ट्रपति शासन लगाया तो आपने वहां कंसोलिडेशन करने का प्रयास किया, झारखंड को रास्ते पर लाने का काम किया। लेकिन इसके आगे की जो लाइन है, वह बड़ी रोचक है। फिस्कल एंड रैवेन्यू डैफिसिट बोलते-बोलते आपने कह दिया कि "The indicators of revenue and fiscal deficits are within the limits prescribed by the FRBM Act." 28 महीने से आपकी सरकार नहीं चल रही थी, 28 महीने से राष्ट्रपति शासन नहीं चल रहा था, 28 महीने से हमारा शासन चल रहा था। इसका मतलब यह है कि स्टेट को फिस्कल डैफिसिट से हमने कंट्रोल रखा, रैवेन्यू में कंट्रोल रखा है, यह सब हमारी देन है। क्योंकि केन्द्र का जो फिस्कल डैफिसिट है वह 5.2 है, हमारा 2.3 है। इसका मतलब यह है कि हमने उसे कंट्रोल रखा है। आपने इसके रीजन्स दिये हैं, रीजन्स यह दिया कि डिवेलपमेंट नहीं हो रहा है। आपने पिछले साल

के बजट एस्टीमेट और रैवेन्यू एस्टीमेट में जो 90 हजार करोड़ रुपये घटाये, क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं कि झारखंड में आपने कितना प्रतिशत पैसा नहीं दिया है।

सेंटर के सर्व-शिक्षा-अभियान में जो 65 और 35 का हिस्सा होना चाहिए था उसमें आपने कितना पैसा नहीं दिया है। आपने हमारा पैसा काटा है। इंदिरा आवास में आपने हमारा पैसा काटा है, वृद्धावस्था पैंशन में आपने हमारा पैसा काटा है, बीआरजीएफ प्रोग्राम में आपने हमारा पैसा काटा है और यही कारण है कि हम पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हमारे ऊपर चार्ज लगा रहे हैं। आज झारखंड के लोगों की स्थिति क्या हो गयी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है। महोदया, आपकी कविताएं भी मैं सुनता रहता हूं। झारखंड के लोगों की स्थिति इस कविता में स्पष्ट है।

"पेट पीठ दोनों मिलकर रहे एक,

चल रहा लकुटिया टेक,

मुट्ठीभर दाने को,

भुख मिटाने को।"

आपके सामने हम तरस रहे हैं कि आप हमें पैसा दीजिए और हम आपके आधार पर बजट बनाते हैं लेकिन आप हमें पैसा देने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। आप हमें ठगने का प्रयास करते हैं। चाहे एक्सिलिरेटेड इरिगेशन बैनिफिट प्रोग्राम हो, चाहे बीआरजीएफ हो, चाहे सेंटर और स्टेट का हिस्सा देने की बात हो, हमें आपने हमेशा भ्रम में रखने का काम किया है। वहां का प्रशासन बजट तो बहुत लम्बे-लम्बे बना रहा है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, मैं बिंदुवार इस पर आना चाहता हूं।

सबसे पहले हैल्थ की बात है। हैल्थ में पूरे देश में 108 नम्बर का एम्बुलेंस चालू हो गयी है लेकिन हमारे यहां आज तक यह फैसला नहीं हो पाया कि यह नोमिनेशन के बेसिज पर दिया जाएगा या टेंडर के बेसिज पर दिया जाएगा। आज आपको एम्बुलेंस कहीं भी, किसी भी अस्पताल में नजर नहीं आयेगी। मैं जहां से सांसद हूं वहां के अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है। देवघर जहां के लिए चार-पांच करोड़ रुपये हर वर्ष जाते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि पांच साल पहले उस अस्पताल को बनाने का काम बंद हो गया है, आज तक वह चालू नहीं हो पाया है। महोदया, वर्ष 2010 में एक हॉस्पीटल का शिलान्यास हो गया, चूंकि इस बजट में दिया गया है कि हम दो मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल बना रहे हैं। यह बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं। क्या आपने वर्ष 2010, 2011, 2012 या 2013 का बजट देखा है? ये बजट आपके देखने लायक हैं? मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि दुमका में वर्ष 2010 में शिलान्यास हो गया, लेकिन आज वर्ष 2013 तक, तीन साल से वहां एक ईंट नहीं रखी गई है और उसके लिए बजट में प्रोवीज़न किया गया है। कहीं भी आपको एएनएम और जीएनएम के स्कूल और कॉलेजिस नहीं दिखाए देंगे। आपने लक्ष्मी लाडली योजना के लिए पैसा दिया है और हेल्थ से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा विषय है। लाडली लक्ष्मी योजना में पैसा दिया जा रहा है, लेकिन जब उसका सैकिण्ड इन्स्टॉलमेंट देने की बात आयी तो वहां बच्चियां ही नजर आयीं। बच्चियां इसलिए नजर नहीं आयीं क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। मृत्यु दर वहां इतनी ज्यादा है। आप किस तरह का हेल्थ का बजट बनाना चाहते हैं। लोगों को वहां सुविधा नहीं मिली है, लेकिन आपने एनआरएचएम के नाम पर बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बना दिए हैं। किसी भी हॉस्पीटल में आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। किसी भी हॉस्पीटल में आपको नर्स और कम्पाउंडर दिखायी नहीं देंगे। किसी भी हॉस्पीटल में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। किसी भी जिला अस्पताल में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी और आप कहते हैं कि हम इसमें बजट दे रहे हैं। यह आपकी भी गलती है, क्योंकि आप एनआरएचएम का पैसा देते हैं और आप कहते हैं कि दस हजार रुपये प्रत्येक गांव में छिड़काव के लिए दिया जा रहा है। कभी आपने देखा है कि क्या वहां डीडीटी का छिड़काव हो रहा है या नहीं? यह झारखण्ड की स्थिति है और इसीलिए मैं चाहता था कि यहां डिस्कशन करके यह बजट पास हो।

महोदय, अब मैं एजुकेशन पर आता हूं। एजुकेशन की क्या हालत है? 203 जगहों पर मॉडल कॉलेजिस बनने हैं, जो कि भारत सरकार को बनाने हैं, लेकिन मॉडल कालेज का एक भी बिल्डिंग आज तक नहीं बना है। पूरे झारखण्ड राज्य में एक भी बिल्डिंग नहीं बनी है। आपने 203 मॉडल स्कूल के लिए जो पैसा दिया है, जो कि प्रत्येक ब्लॉक हेडक्वार्टर में बनना है। उस मॉडल स्कूल के लिए 42 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार देती है। जबकि सारा का सारा पैसा केन्द्र सरकार को देना है। एक भी स्कूल ऐसा नहीं है, जिसमें आपको टीचर नजर आएगा। पिछले साल भी झारखण्ड सरकार ने कहा कि अपने बजट में 138 करोड़ रुपये रखते हैं। हम लगातार लिखते रहे, क्योंकि शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से हमारा डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है और इसलिए हमारे यहां मॉडल कॉलेज होना चाहिए। मॉडल कॉलेज के बारे में केन्द्र सरकार कहती है कि 65 परसेंट केन्द्र सरकार देगी और 35 परसेंट राज्य सरकार देगी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछले साल के और इस साल के बजट में एक भी मॉडल कॉलेज कंसीव नहीं हुआ है। एक भी मॉडल कॉलेज नहीं हुआ है। लोगों को पढ़ने के लिए टीचर नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। पंखे-बिजली का तो कोई सवाल ही नहीं है। सेमेस्टर बढ़िया से नहीं चल रहा है। यह हालत प्राइमरी एजुकेशन की है। यह हालत सर्व शिक्षा अभियान की है, मिड डे मील की है। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए आपको टीचर ही नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसका एप्वाइंटमेंट ही नहीं हुआ है। आपको कहीं भी आईटीआई प्रोपर फंक्शन करती नज़र नहीं आएगी। इन्होंने इस बजट में कहा कि पोलिटेक्नीक खोलेंगे। सात जगह पीपीपी मोड पर और तेरह जगह, आपको पता है कि वह पैसा कब का है। जिस चीज की घोषणा आपने बजट में की है, वह पैसा वर्ष 2010 से पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार बारह करोड़ तीस लाख रुपया देने वाली है और उसमें दो करोड़ की पहली किस्त वर्ष 2010 से पड़ी है। आपने कभी पूछा कि वर्ष 2010 से तुमने पैसा रखा है और क्यों नहीं आज तक पोलिटेक्नीक बन पाया है। आज यह हालत झारखंड की है। आपको एक भी इंजीनियरिंग कालेज प्रोपर फंक्शन करते हुए नहीं नजर आएगा। एक पोलिटेक्नीक, आईटीआई आपको प्रोपर फंक्शन करती नजर नहीं आएगी। झारखंड सरकार ने इस साल को कौशल विकास साल बनाया हुआ है। आप कारपेंटर की बात छोड़िए, लौहार की बात छोड़िए, सुनार की बात छोड़िए, राजमिस्त्री की बात छोड़िए, बढ़ई की बात छोड़िए क्योंकि उनके लिए तो स्किल डेवलपमेंट का सवाल ही नहीं है। जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनके लिए भी कुछ नहीं है। झारखंड की आप लोगों ने क्या हालत बना रखी है?

इसके बाद मैं रूरल डेवपलमेंट की बात कहना चाहता हूं। आज तक 9 गवर्नर वहां बदले जा चुके हैं। जब से मैं सांसद बना हूं, तब से वर्तमान के चौथे गवर्नर हैं। आप स्वयं अस्थिरता लाना चाहते हैं। जब मैं एमपी बना तब â€¦* थे, उसके बाद ..... * बने, उनके बाद ..... *और अभी ... *हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नाम रिकार्ड में नहीं जाएंगे।

श्री निशिकांत दुबे : चार साल में चार गवर्नर बदले हैं। आप स्वयं अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। क्या ..... * को हमने पैदा किया? आपने मॉडल ला दिया। क्या हमने कहा कि क्रप्शन कर लीजिए।

14.00 hrs.

यह भी हम ही ने कहा कि करप्शन कर लीजिए। हम ही ने कहा कि झारखंड को लूट लीजिए। रूरल डवलपमेंट का लीजिए। रूरल डवलपमेंट में आपको मनरेगा में लगेगा, मैं इस सदन में बड़ी गंभीरता के साथ निगरानी के चेयरमैन के नाते कहना चाहता हूं और मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि वहां कितना करप्शन है?

निगरानी समिति के चेयरमैन के नाते मैंने वर्ष 2009 में 7 करोड़ रुपये का बैन मनरेगा में लगा दिया। बड़ा अच्छा हो गया, उसमें करप्शन था। डीडीसी की रिपोर्ट आ गई। झारखंड हाईकोर्ट में डिसीजन हो

ÂÂÂ_____

* Not recorded

गया कि कोई पैसा नहीं दिया जाएगा जब तक निगरानी समिति तय नहीं करेगी और कल परसों से अभी मनरेगा कमिश्नर ने आदेश दिया है कि उसका काम चालू कर दीजिए। 7 करोड़ रुपये का पेमेंट कर दीजिए। करप्शन नहीं है। कोई बात नहीं है। मनरेगा का काम चल रहा है। कोई बात नहीं है। यह झारखंड की स्थिति है। पुल-पुलिया के बारे में आप कह रहे हैं कि पैसा दे रहे हैं। पुल-पुलिया में क्या आप यह बता सकते हैं कि वहां जो रीजन है, रांची के अलावा रांची और जमशेदपुर, खरसांवा के इलाके को छोड़ दीजिए, सिल्ली के इलाके को छोड़ दीजिए, यह बताइए कि संथाल-परगना के 6 जिले में कितने पुल और पुलिया तथा कितनी रोड्स सैंक्शन हुई हैं? यह बताइए कि पलामू, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में कितने पुल-पुलिया और रोड्स सैंक्शन हुई हैं? आपको आश्चर्य होगा और लगेगा कि एक क्षेत्र विशेष में हमने रूरल डवलपमेंट का सारा पैसा पुल-पुलिया के लिए दे दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिदम्बरम साहब को बताना चाहता हूं कि 17 जिले हैं जो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में हैं। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान का मतलब होता है कि 250 से ऊपर की जो आबादी है, वह रोड से कनैक्ट हो जाएगी, सेन्ट्रल गवर्नमेंट उसका पैसा देगी और बाकी जो 7 जिले हैं, उन 7 जिलों के लिए राज्य को सोचना चाहिए लेकिन राज्य ऐसा नहीं सोच रहा है और वह बंदरबांट कर रहा है। निशिकांत दुबे ने कुछ कहा तो उसको कर दीजिए, यशवंत जी ने कहा तो उसको कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? यदि आप राज्य का समग्र विकास करना चाहते हैं तो उस विकास के लिए आपको रूरल डवलपमेंट में कहां रोड बननी है, कहां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड नहीं जा रहा है, वहां आप मुख्य मंत्री सड़क योजना से आप उसको जोड़ने का प्रयास करिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बंदरबांट है। करप्शन है। कितने लोग इसमें इंवाल्वड हैं? आपको इसकी स्थिति पता नहीं होगी।

इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में आप प्रत्येक जिले को, 17 जिले को मान लीजिए कि आप 25 से लेकर 40 करोड़ रुपये तक देते हैं। बाकी जो 7 जिले हैं, वे 7 जिले क्या करेंगे? क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है? थाने में गाडियां नहीं हैं। आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा आज हम नक्सलवाद से जूझ रहे हैं और नक्सलवाद से यदि जूझ रहे हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसके लिए थाने में गाड़ियों की क्या हालत है? एसआरए जिला होने के नाते उसके फाइनेंस की क्या स्थिति है और क्या बन रहा है? केवल पुलिस आधुनिकीकरण के नाम पर 1500 करोड़ रुपया किसी एकाउंट में रखा हुआ है। वहां कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन वह खर्चा दिखाया जा रहा है कि पुलिस मॉडरेनाइजेशन के नाम पर 1500 करोड़ रुपया हमने दे दिया और वह खर्च हो गया। इस तरह से जो पैसे को मिसयूज करने की टेंडेंसी है, इसके बारे में सोचिए क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है, वह बंग्लादेश से जुड़ा हुआ है। हमारा जो बॉर्डर है, वह नेपाल से जुड़ा हुआ है और जब आप गृह मंत्री थे तो मैं बोलते बोलते थक गया हूं कि मैं जिस संथाल-परगना से आता हूं, उसका बॉर्डर बंग्लादेश और नेपाल से जुड़ा हुआ है। जो नेपाल के पूर्व प्रधान मंत्री थे, उन्होंने खुद कहा है कि दस साल जो वो एग्जाइल में रहे, पांच साल वह संथाल-परगना में रहे, संथाल-परगना नक्सेलाइट पैदा करता है और उसके बाद वह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आध्र प्रदेश के लिए डिसपर्स होता है और इस तरह से पूरे देशभर में वहीं से जाता है। बंग्लादेशी इंफिल्ट्रेटर्स जो आते हैं, उनका सबसे बड़ा शरणस्थली वही है लेकिन आपके कान पर जूं ही नहीं रेंगती है। आपको लगता है कि स्टेट का विषय है और स्टेट कहता है कि सेंटर का विषय है। बहुत अच्छा विषय है कि हम आपसे यहां डिसकस कर रहे हैं।

इसके बाद ट्यूरिज्म आता है। माइन्स और मिनरल्स पर मैं बाद में आऊंगा कि आप किस तरह से हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ट्यूरिज्म की बात पर अब मैं आता हूं। देवघर जहां से आता हूं, मेगॉ ट्यूरिस्ट डेस्टीनेशन देवघर हो गया। 2010 से 25 करोड़ रुपया मेगॉ ट्यूरिस्ट डेस्टीनेशन के लिए दिया जाता है। वर्ष 2010 से 12.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। क्यों 40 करोड़ रुपये की लागत से कॉम्पलैक्स बनना है? वर्ष 2013 तक उसमें काम चालू नहीं हुआ है। चाहे कोई भी ट्यूरिस्ट डेस्टीनेशन ले लीजिए। पारसनाथ मैंने आपको बताया। उसमें कोई काम चालू नहीं हुआ है। बॉस्कीनाथ आपको बताया यानी जो भी है, मुनरू है, रांची है, सब जगह बड़े बड़े सेंटर आपको नज़र आ रहे हैं। एक भी प्रोजेक्ट में काम शुरु नहीं हुआ और इस साल जो स्टेट प्लान का बजट है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 31 मार्च तक उसमें एक भी योजना सैंक्शन नहीं होने वाली है। जो केन्द्र सरकार पैसा दे रही है, वह पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। केन्द्र सरकार अपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देने के कारण या पैसा जमा होने के कारण यदि झारखंड सरकार से पैसा वापस मांगती है कि आप दोबारा अगली योजना में ले लीजिएगा क्योंकि झारखंड की तरह हम चौपट व्यवस्था में नहीं चलना चाहते हैं तो राज्य उसको पैसा लौटाने के लिए तैयार नहीं है। यानी जो पैसा दिया गया वह मेरा ही पैसा है। यह टूरिज्म का हाल है।

महोदय, एक भी योजना चालू नहीं है। मान लीजिए अगर बन भी गया तो कब चू जाएगा पता नहीं। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने खुद ड्रिंकिंग वाटर के बारे में कहा है 3.7 परसेंट पाइप वाटर चल रहा है। मैं देवधर से सांसद हूं, वहां जेएनएनयूआरएम की तरफ से वाटर प्रोजेक्ट चल रहा था जो दिसंबर, 2009 में पूरा होना था। यह दिसंबर, 2013 तक पूरा हो पाएगा या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आपने 19 करोड़ रुपए का पहला इंस्टालमेंट दे दिया, दूसरा नहीं दे रहे हैं। कन्सोलिडेटिड फंड से पैसा दिया भी गया है, उसके डीपीआर का सोर्स ऐसा है कि अभी जब वह प्रोजेक्ट कम्पलीशन की हालत में है तो कहा जाता है कि सोर्स ही नहीं है, पानी ही नहीं आ पाएगा। आप कैसे विकास करेंगे?

महोदय, वहां चापाकल गड़ता है, एमपी और एमएलए के कहने से पांच-पांच चापाकल प्रत्येक पंचायत में दे दिए। अब बात आती है कि चापाकल कैसे गड़ता है? एक जगह का चापाकल उठाकर दूसरी जगह गाड़ दिया जाता है क्योंकि कोटा पूरा करना है। यह स्थिति है। किसी भी गांव में कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता है। मैं दूसरी जगह की बात नहीं कहता, यशवंत जी या उपाध्यक्ष महोदय आप बताएंगे। मेरे यहां जितने रूरल वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें से एक भी चालू नहीं है। यह पिछले दस साल से है। मैंने अपने यहां कहा है कि सारे अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। यह रूरल वाटर की स्थिति है और आप कहते हैं कि हम पीने का पानी देंगे और

इसमें 200 से 300 करोड़ रुपया एलोकेट कर दिया गया है। आपने क्या एलोकेशन की हैं?

महोदय, यह कहा जा रहा था कि इरीगेशन में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यह बताया गया है कि ये-ये प्रोजेक्ट पूरे करेंगे और 1 लाख 45 हजार हेक्टेयर बढ़ेगा। अजय बैराज का उद्घाटन 2011 में हुआ था। 2013 में क्या बढ़ाया है? हमारे यहां पुरासी योजना चल रही है, सूखा पठार है, 1978-78 में उढ़ई का शिलान्यास हो चुका है। सब में पैसा जा चुका है। कोई भी प्रोजेक्ट चालू स्थिति में नहीं है, चाहे पलामू, गुमला, रांची, संथाल परगना, गुमानी या स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट हो। स्वर्णरेखा तो और बड़ा केस है। आज से एक साल पहले यानी 2011-12 में 335 करोड़ रुपया एआईबीपी में दिया। एआईबीपी से काम चालू हुआ। 2012-13 में एक रुपया भी एलोकेट नहीं किया गया। झारखंड सरकार ने बजट बना लिया कि एआईबीपी में पैसा मिलेगा। स्वर्णरेखा के कारण कोई दूसरा प्रोजेक्ट एस्कलेटिड इरीगेशन प्रोग्राम में नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसका पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी चपरासी की तरह चक्कर काट रहे हैं। किसी के जूं नहीं रेंग रही है।

आप वित्त मंत्री हैं, आप बताएं कि उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? उसी तरह से पुनासी डैम 40 साल से चल रहा है। उढ़ई का मधु लिमये जी ने 1978 में शिलान्यास किया था। सूखा पठार का 1977 शिलान्यास हुआ था। बटेश्वर पंप नहर योजना को 2013 में पूरा होना था शायद ही पूरा हो पाए। इस तरह इरीगेशन की यह स्थिति है। सीरीज़ आफ चैक डैम नाले पर नजर नहीं आएगा। उससे कोई भी पानी नहीं ले सकते हैं। रिहेबिलिटेशन और रेस्टोरेशन प्रोग्राम में, ट्रिपल आर पालिसी में जिसमें बांध और तालाब बनना है, एआईबीपी में एक बांध का भी क्लियरेंस नहीं होता है यदि हो भी जाए तो उसका ऐसा बुरा काम होता है कि पानी नहीं मिलेगा। लिफ्ट इरीगेशन के जितने प्रोजेक्ट हैं, जिस भी एरिया में हैं, एक भी प्रोजेक्ट चालू नहीं है, चाहे माइनर या मेजर इरीगेशन हो, आप क्या करेंगे?

महोदय, राजीव गांधी बिजली परियोजना में जितने भी ट्रंसफार्मर हैं, झारखंड के जितने सांसद हैं ज्यादातर सभी सांसदों के क्षेत्रों में ट्रंसफार्मर जले हुए हैं। कभी कहते हैं कि आर्डर दे दिया है जनवरी में आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा। हम आशा से देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है जब चुनाव में जाएं तब भी न आए। एक कंपनी को पैसा दे देते हैं। एक नया पावर प्लांट नहीं आ रहा है। यह बिजली की स्थिति है। हमारी बात कौन सुनेगा? ...(व्यवधान) यह सब्जेक्ट ही तो है। आपने बिजली के लिए पैसा एलोकेट किया है तो यह कौन देगा? हमारे यहां 1990 से ग्रिड बन रहा है। आपने खुद ही लिखा है कि हम राष्ट्रपति शासन में चीजें ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या केन्द्र का पैसा हम देंगे? एआईबीपी का पैसा आप देंगे। आप जो एडवरटाइजमैन्ट कर रहे हैं, उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल और माननीय प्रधान मंत्री जी का कह रहे हैं कि आपने एकदम पूरी व्यवस्था ठीक कर दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नरेगा, मनरेगा, बिजली, पानी सब ठीक कर दिया। हम रोज जो एडवरटाइज देख रहे हैं, क्या यह कोई तरीका है। राष्ट्रपति शासन क्या कोई चुनी हुई सरकार हैं? आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप इन चीजों को सुनना भी नहीं चाहते।

मुझे हरिवंशराय बच्चन की एक बहुत अच्छी कविता याद आ रही है - "तोड़-मरोड़ विरल लतिकाएं, नोंच-खसोट कुसुम कलिकाएं, जाता है अज्ञात दिशा, उड़ जाओगे, क्या तुम तूफान समझ पाओगे।"...(व्यवधान) यह मैं आपके लिए कह रहा हूं। यह तूफान है, झारखंड की जनता का यह तूफान है। आपने जो ...पैदा किया और वहां के पैसे को लूट लिया, हवाला में जो पैसा चला गया, वह जो पैसा नहीं आ पा रहा है...(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM : You should have made Shri Yashwant Sinha Chief Minister.

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Thank you very much.

श्री निशिकांत दुबे: यानी आप नहीं चाहते कि आपकी जगह पर यशवंत जी जाएं, यानी यशवंत जी को देश का वित्त मंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। आप यशवंत जी को मुख्य मंत्री पद पर सिमटाना चाहते हैं।

SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, he is condemning his own Government for the last 12 years. I do not know why he is continuing in this vein! We are trying to help you. Try to take the help of the Central Government; hold elections quickly; and elect a Government. If you want to condemn your own Government for the last 20 minutes, you might do so for the next 20 minutes and I have no objection.

SHRI NISHIKANT DUBEY: I am not condemning my Government. You said that the President's Rule is always better. Hence, I am saying this.

SHRI P. CHIDAMBARAM : No, I did not say so. It is not my fault.

SHRI NISHIKANT DUBEY: It is your fault. हमारे यहां माइंस और मिनरल्स हैं।

SHRI P. CHIDAMBARAM : I started by saying that the President's Rule is not the answer. ...(*Interruptions*)

श्री निशिकांत दुबे: महोदय, वित्त मंत्री के नाते यह बतायें, यह कहते हैं कि आपके यहां 30 परसैन्ट कोयला है, 30 परसैन्ट आयरन ओर है। हमारे यहां यूरेनियम और बॉक्साइट भी है। हमारे यहां ये जो पैसा देते हैं, वह मात्र तीन हजार करोड़ रुपये देते हैं। जीडीपी में कितना परसैन्ट स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेन्ट इंडस्ट्रीज, बॉक्साइट इंडस्ट्रीज या कोयला इंडस्ट्रीज महत्व रखते हैं, इनके यहां का पावर प्लान्ट बंद हो जायेगा। कितना परसैन्ट हम जीडीपी में देते हैं और आप उसके बदले हमें तीन हजार करोड़ रुपये देते हैं। रेलवे को चालीस परसैन्ट रेवेन्यू हम देते हैं। रेलवे हमारे यहां एक भी प्रोजैक्ट नहीं करती है। इसमें दोष आपका है। क्या बीआरजीएफ का पैसा राज्य का दोष है, क्या एआईबीपी का पैसा राज्य का दोष है, क्या सर्व शिक्षा अभियान राज्य का दोष है, क्या इन्दिरा आवास राज्य का दोष है? आप बताइये, 90 हजार करोड़ रुपये का केन्द्र ने जो नुकसान किया है, जो पैसा काटा है, उसमें यदि सबसे ज्यादा किसी को धोखा दिया है तो केवल झारखंड को दिया है। हमारी सरकार दस साल नहीं रही है। तीन साल आपकी सरकार रही है और पांच साल ये सरकार चला रहे हैं। हमारी सरकार तीन साल रही है।...(व्यवधान) आप विस्थापन की बात कर रहे हैं। नगरी में यदि लोगों ने पैसा ले लिया। डा.अजय जिस पार्टी के सांसद है, मैं उन्हें छेड़ना नहीं चाहता था। नगरी में लोगों ने पैसा ले लिया, वहां कालेज बनेगा कि नहीं, कालेज किसके लिए बनेगा, झारखंड के लोगों के लिए बनेगा या दूसरों के लिए बनेगा? वह शेडयूल फाइव की बात कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा कि शेडयूल्ड फाइव में माइन्स नहीं होनी चाहिए। आपके अध्यक्ष महोदय चूंकि यहां के माननीय सांसद है, वह वहां धरने पर बैठ गये, बहुत बढ़िया बैठ गये। शेडयूल फाइव में पैनएम को किसने क्लियरेन्स दिया। मुख्य मंत्री के नाते माननीय बाबू लाल मरांडी जी ने दिया और चूकि इस सदन के सदस्य हैं, इसलिए उनकी पार्टी के सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड लुटवाने में आपका भी उतना बड़ा योगदान है और यहां आकर भाषण दे रहे हैं कि विस्थापन पर बातें

नहीं होनी चाहिए। यहां आकर भाषण दे रहे हैं कि शेडयूल फाइव मे माइन्स नहीं होनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि देश कैसे चलेगा, झारखंड का डैवलपमैन्ट कैसे होगा, उसके बारे में आप समग्र सोच रखिये। यदि स्टील अथारिटी का कार्यालय वहां नहीं है, हैड ऑफिस नहीं है तो इसमे केन्द्र का दोष है। यदि कोल इंडिया का हैड ऑफिस नहीं है तो इनका दोष है। टाटा यदि मुम्बई में हमारा पैसा लूटकर वहां इंकम टैक्स दे रहा है तो इसमें दोष है, क्योंकि यह सब झारखंड का पैसा है। इसके लिए डिमांड करनी चाहिए।

जहां तक पेंशन फंड का सवाल है। पेंशन के लिए इनके यहां अधिकारी हैं। जिस काडर का जो अधिकारी है, उसे यह निर्णय करने का अधिकार नहीं था। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश भर में 1956 के बाद जितने राज्य बने हैं, उनका पेंशन का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। यह भी बता दें कि यह राज्य का विषय है। सन् 1956 के बाद से सारे राज्य जनसंख्या के आधार पर हैं। हमारे यहां एंप्लाई के आधार पर हो गया क्योंकि दो एंप्लाई बिहार रह गए और एक एंप्लाई यहां रह गया। बिहार की असेंबली का किसी ने एक अमेंडमेंट दे दिया। यदि इस अमेंडमेंट को किसी ने देखा नहीं तो आप उसकी गलती सुधारेंगे या नहीं सुधारेंगे? दस हज़ार करोड़ रूपये का नुकसान है। हम मात्र सात-आठ हज़ार करोड़ रूपये का अपना रेवन्यु जनरेट कर पाते हैं। हम विकास में लगाना चाहते हैं, उसमें यदि दस हज़ार करोड़ रूपये आप ले लीजिएगा, यह आपका विषय नहीं है? उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय का विषय नहीं है? दूसरा विषय यह है कि यदि हमारे झारखण्ड में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ तो वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण नहीं हुआ है। यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण चुनाव नहीं हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन है? लेकिन आपने मेरा छह हज़ार करोड़ रूपये रख लिया है। आप पैसा देने को तैयार नहीं है। आप मिनरल माइंस में रॉयल्टी नहीं देंगे। आप पेंशन फण्ड में हमारे साथ धोखा करेंगे। पंचायत चुनाव नहीं हुआ है, उसके कारण हमारे साथ समस्या है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमारे यहां 70 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। 73-74 प्रतिशत महिलाएं मालन्युट्रिशन की शिकार हैं। हमारे यहां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का फर्स्ट फ़ेज का रोड़ आज तक पूरा नहीं हुआ है। मनरेगा में भयंकर लूट है। जब से राष्ट्रपति शासन शुरू हुआ है, तब से और लूट हो रही है। माननीय जयराम रमेश जी उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री निशिकांत दुबे: हमारे यहां जीडीपी नहीं बढ़ पा रही है। माइंस में कुछ नहीं हो रहा है। 70 प्रतिशत लोग गरीब हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं और पिछड़े हैं। मेरा यह कहना कि यदि किसी एक राज्य को सबसे पहले स्पेशल स्टेट्स मिलना चाहिए था, वह झारखण्ड को मिलना चाहिए था। यदि हम से पहले आप किसी को स्पेशल स्टेट्स दे देंगे तो हम वहां से माइंस, मिनरल और कोयला को लाल कर देंगे। हम आपको कोयला नहीं देंगे। हम आपको आयरन-ओर नहीं देंगे, बॉक्साइट नहीं देंगे। On the floor of House हम कह रहे हैं कि हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि यह देश ठप्प हो जाएगा क्योंकि झारखण्ड में इतनी ताकत है। इस देश को रोकने का यदि किसी एक राज्य में अधिकार है, तो वह झारखण्ड में है। हम आपको कुछ नहीं देंगे? ...(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Are you holding a threat to the country?

SHRI NISHIKANT DUBEY: Yes, if you will not give anything to Jharkhand or the people of Jharkhand, then it is a threat to the country. It is because we are suffering for the last 65 years.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not get involved in cross-talks here.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, please conclude now.

SHRI P. CHIDAMBARAM: It is because of their own Government. It is your fault.

SHRI NISHIKANT DUBEY: No, it is not my fault.

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश): उपाध्यक्ष जी, आप भी झारखण्ड के रहने वाले हैं। मैं इस इल्ज़ाम का पूरा खण्डन करना चाहता हूँ। पिछले दो साल से मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में आया हूँ, तब से झारखण्ड के साथ कोई भेद-भाव नहीं हुआ है। ग्रामीण सड़कों के बारे में, मनरेगा के बारे में, इंदिरा आवास योजना के बारे में झारखण्ड को विशेष दर्जा दिया गया है। सांसद की ऐसी धमकी देना उचित नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member, please conclude now.

...(*Interruptions*)

श्री निशिकांत दुबे: हमारे सत्तर प्रतिशत लोग यदि गरीब हैं, यदि बीपीएल हैं तो इसमें मेरा दोष है? ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री निशिकांत दुबे: उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुष्यंत कुमार की एक कविता कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि -

" इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं हमारे, जिस तरह ये टूटे हुए आइने दिखते हैं।
आपने कालीन देखा होगा, इस देश ने कालीन देखा होगा, लेकिन मेरे पांव कीचड़ में हैं। उस कीचड़ से निकालने के लिए हमें प्रयास करने दीजिए।
"

श्री जयराम रमेश : उपाध्यक्ष महोदय, चुनी हुई सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें माननीय सदस्य से आती हैं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत झारखण्ड राज्य के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया है।

माननीय सदस्य जिस तरह से लगातार उल्लेख कर रहे थे और योजनाओं के लागू न होने के कारणों की बात कर रहे थे, उसमें स्वाभाविक रूप से अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे थे और वह स्वाभाविक है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर बोलिए।

श्री जगदम्बिका पाल : अभी दो महीने पहले तक उन्हीं की सरकार थी। जिन योजनाओं का पैसा गया है, उनकी ही सरकार में गया है। इस संघीय ढांचे में यह व्यवस्था है कि जो पैसा केंद्र सरकार से जाता है, उस पैसे को खर्च करने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार उसको खर्च करती है। हमने वर्ष 2012-13 में जो पैसा दिया, 11,22,790 लाख इनका बजट अनुमान था, उससे बढ़ाकर केंद्र सरकार ने पैसा दिया, जो केन्द्रीय अनुदान और सहायता है, मैं राज्य के उनके बजट की बात नहीं कर रहा हूं, केन्द्रीय सरकार से जो सहायता मिली है, मैं उसकी वर्ष 2012-13 की बात कर रहा हूं। वर्ष 2012-13 में जो बजट अनुमान था, वह 11,22,790 था और हमने 11,32,191 लाख दिया है। मैं समझता हूं कि इनको तो धन्यवाद देना चाहिए था, इनको वित्त मंत्री जी को बधाई देनी चाहिए थी कि झारखण्ड राज्य के लिए, जैसा माननीय मंत्री जयराम रमेश जी ने भी कहा कि चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हों, सबमें हमने दिया है। मैं समझता हूं कि आज आप बहुत गुस्से में थे, मैं समझता हूं कि वह गुस्सा इसलिए था कि जिस तरह के सुझाव आप अपनी पिछली सरकार के मुख्यमंत्री जी को देते थे, शायद वे सुझाव नहीं मानते रहे होंगे, तो वह गुस्सा आज परिलक्षित हो रहा है। अन्यथा मैं समझता हूं कि वर्ष 2000 में झारखण्ड राज्य का गठन हुआ और वर्ष 2004 तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर वास्तव में झारखंड के लिए दर्द था, तो वर्ष 2000 से 2004 में क्यों नहीं झारखण्ड राज्य को भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार ने स्पेशल स्टेटस दिया। आज हमारे मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने एक तरह से स्पेशल स्टेटस दिया है। हमने ग्रामीण सड़कों में दिया है।...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे: एक तरह क्या हुआ, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस होता है।

श्री जगदम्बिका पाल: आपने वर्ष 2000 से 2004 तक, जिसे वित्त मंत्री जी बनाने की बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप अपनी बात कह चुके हैं।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: आप खड़े क्यों हो गए? निशिकांत जी, आपका भविष्य उदीयमान है, कम से कम आपने कहा है, तो उसको सुनिए भी। आपने कृषि पर बहुत जोर दिया। आज जो सेंट्रल स्कीम हैं, एडीबी, उस एडीबी में वर्ष 2013-14 में और कृषि में जो 66 परसेंट आपकी आबादी है, हमने इस बार के बजट में प्रावधान बढ़ाया है। आप उस राष्ट्रपति शासन की आलोचना कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने कहीं नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन अच्छा है। आपने कहा कि माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन है, इसलिए हम तारीफ कर रह हैं। वित्त मंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन अच्छा है। राष्ट्रपति शासन कोई उपाय नहीं है, हम चाहते हैं कि वहा लोकप्रिय सरकार रहे और आज भी हम चाहते हैं कि वहां इसकी संभावनायें हों। आखिर राष्ट्रपति शासन लाने के लिए कौन गुनहगार है, कौन जिम्मेदार है? आज पूरा देश जानता है कि अगर झारखण्ड में राष्ट्रपति शासन आया है, तो वह केवल आपके कारण आया है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, टोका-टाकी मत कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: वहां आपकी सरकार थी, इसे कौन नहीं जानता है? जिस समय चुनाव के बाद वहां पर सरकार बनी, तब आप उनके साथ सरकार में शामिल थे। आपको यह बर्दाश्त नहीं हुआ, आप वहां की जिस सरकार में शामिल थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के थे और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री थे और आपने उसे नहीं चलने दिया। आपने उस सरकार को गिराया और उस सरकार को गिराकर फिर राष्ट्रपति शासन की स्थिति बनी। फिर उन्हीं के साथ मिलकर जब आप मुख्यमंत्री बने, आप उनको उपमुख्यमंत्री बनाते हैं और जब वे कहते हैं कि 18 महीने आपने शासन कर लिया, 18 महीने अब हमको शासन करने दीजिए। जब आपने उन्हें यह मौका नहीं दिया...

उपाध्यक्ष महोदय : आप बजट पर बोलिए।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं बजट पर ही बोलने जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो आप राष्ट्रपति शासन पर बोल रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, जब वे कह रहे थे तो उनकी बात का जवाब तो आ जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : वह चर्चा तो हो चुकी है।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य की बात उठायी, आज स्वास्थ्य में हमने 776.23 करोड़ रूपये आबंटित किये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि स्वास्थ्य में सबसे बुनियादी आवश्यकता क्या है, आज सबसे बुनियादी आवश्यकता यह है कि मॉर्टेलिटी रेट कम हो, मातृ मृत्यु दर कम हो। आज राष्ट्रीय औसत क्या है, आज मातृ मृत्यु दर का राष्ट्रीय औसत 212 है और झारखण्ड में मातृ मृत्यु दर 261 है। जहां राष्ट्रीय औसत 212 है, उसके सापेक्ष झारखण्ड में मातृ मृत्यु दर 261 है, वहां 261 महिलाओं की मौत हो रही है। जैसा हमारे अजय कुमार जी ने कहा कि वर्ष 2000 से आज तक वहां आपकी सरकार थी, कभी भी झारखण्ड में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अगर आज भी आप वहां पर प्रसव के समय हो रही महिलाओं की जिन्दगी को नहीं बचा सकते, आप जच्चा-बच्चा के जीवन की रक्षा नहीं कर सकते तो झारखण्ड की जनता आपको कभी कुबूल नहीं करेगी। आप कहते हैं कि स्वास्थ्य में पैसा नहीं दिया गया। आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय औसत क्या है? आज राष्ट्रीय औसत महिलाओं की मृत्यु दर की 212 है और झारखंड की 261 है। इसके लिए क्या हम ज़िम्मेदार हैं? आप केवल मधु कोड़ा का नाम लेते रहे। आपके अर्जुन मुण्डा जी तो अभी तक मुख्य मंत्री थे। जितने भी मुख्य मंत्री हुए, आपके ही भारतीय जनता पार्टी के थे। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कमोबेश रही। जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, या तो वे मुख्य मंत्री बने। कांग्रेस ने कभी आयाराम गयाराम नहीं किया और कांग्रेस ने वहाँ कभी सरकार बनाने का काम नहीं किया। आप लूटने की बात कह रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं आपकी तरफ देखूँगा नहीं, मैं चेयर की तरफ ही देखूँगा। जो लूटने की बात आप कह रहे हैं, वह सवाल आपको अपने नेताओं से पूछना होगा जिनको आपने दायित्व दिया, जिनको आपने ज़िम्मेदारी दी कि उस राज्य में मिनिरल की खरीद और लूट क्यों हुई। आपने शिक्षा की बात की। क्या आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा ड्रापआउट किस राज्य में हैं - झारखंड में हैं। इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? राज्य सरकार ज़िम्मेदार है। अभी मैं पैसा बताऊँगा कि कितना मिला है। आपको मैं हर मद का पैसा बताऊँगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो बोल चुके हैं, उनको अपनी बात कहने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या है, सबसे घटिया स्तर के शिक्षक हैं। आप शिक्षक तैयार नहीं कर पाए, बी.एड. कॉलेज खोल नहीं पाए। दस सालों में जो हमने सरप्लस स्टेट बनाया था जिस तरह से वहाँ के खनिज और मिनिरल्स की दुहाई दी जाती है, उस सरप्लस स्टेट में आप शिक्षक प्रोडयूस नहीं कर पाए, बी.एड. कॉलेज नहीं खोल पाए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए टीचर्स नहीं दे पाए, सबसे ज्यादा ड्रापआउट बच्चों का वहाँ है। वहाँ बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल से वंचित हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : मान्यवर, मैं बजट की बात कर रहा हूँ, मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूँ। आप विकास की बात कहते हैं। मैं कहता हूँ कि भारत सरकार क्या नहीं कर रही है? आप जिस देवघर की बात कर रहे हैं कि देवघर में पूरे देश और दुनिया के लोग आते हैं, उस देवघर में बिल्कुल देश और दुनिया के लोगों की आस्था है। लेकिन उस देश और दुनिया की जिनकी आस्था है, जिस देवघर की आप झारखंड में बात करते हैं, वहाँ हवाई अड्डा देने का काम इसी कांग्रेस और यूपीए सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ कि आप इस बात से सहमत होंगे। ...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे: उसके लिए झारखंड सरकार ने कहा था कि 50 करोड़ रुपये देंगे। ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: लेकिन अभी तक नहीं दिया। ...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे: कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अरे! इस तरीके से हमने तो नही देखा, कम से कम भारत का संस्कार है। अगर कहीं सिविल एयरपोर्ट मिल गया हो, वह हिन्दुस्तान से एयर सर्किट पर जुड़ गया हो उसके लिए कह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपये दिया है। एक एयरपोर्ट कितने का बनता है इनको अंदाज़ है?

श्री निशिकांत दुबे: हाँ, अंदाज़ है।

श्री जगदम्बिका पाल: कितना अंदाज़ है?

श्री निशिकांत दुबे: 350 करोड़ रुपये।

श्री जगदम्बिका पाल: उसमें से 50 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं और उसमें अभी तक झारखंड सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया है। ...(व्यवधान)

अभी आप टूरिज़्म में मैगा प्रोजैक्ट्स की बात कर रहे थे। आज भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय ने अगर मैगा प्रोजैक्ट में 40 करोड़ रुपये भी दिए तो उस मैगा प्रोजैक्ट में जो कार्यदायी संस्थाएँ होती हैं वे राज्य की होती हैं। ...(व्यवधान) मैं कहता हूँ मेरे कपिलवस्तु में भी पाँच करोड़ रुपये ही दिये। आप मुझसे ज्यादा ले गए। लेकिन आज तक राज्य सरकार यह तय नहीं कर पा रही कि हम किस कार्यदायी संस्था से काम कराएँ। इसके लिए राज्य सरकार ज़िम्मेदार है। आप भारत सरकार को बधाई दीजिए। पर्यटन स्टेट का सब्जैक्ट है, एजुकेशन कनकरैन्ट का सब्जैक्ट है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जैक्ट है। हम राष्ट्रीय कृषि विकास नीति के अंतर्गत पर्याप्त

पैसा दे रहे हैं, विभिन्न योजनाएँ दे रहे हैं। आप यह तो देखिये कि हमने वार्षिक परिव्यय को कितना बढ़ाया है। आप कह रहे हैं कि वार्षिक परिव्यय घटा दिया जबकि इस बार हमने 6 प्रतिशत वार्षिक परिव्यय बढ़ाया है। इसी तरह से हमने इनके स्टेट प्लान को बढ़ाया है। हमने हर चीज़ में वृद्धि की है। मैं कहता हूँ कि इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? अगर पैसा भारत सरकार से गया और भारत सरकार से ये पैसा खर्च न कर पाएँ या यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट न दे पाएँ तो जब तक यूसी नहीं देंगे, तब तक दूसरी किस्त नहीं मिलेगी। इनको पिछले मुख्य मंत्री को कहना चाहिए था कि पैसा भारत सरकार से जा रहा है और उसमें पैसा एक्सलरेटेड इंटीग्रेटेड बैनिफिट स्कीम में गया। आप जानते हैं कि एआईबीपी का जो पैसा था, वह आप खर्च नहीं कर पाए। आप चैकडेम की बात कर रहे हैं। हमने इस बार बजट बढ़ाया है और चैकडेम बनेंगे। आप निश्चित तौर से संतुष्ट होंगे। आपको आश्वासन मिल गया है कि बहुत जल्दी चुनाव हो जाएंगे। हम सब यह मानकर चल रहे थे कि शायद दो-चार-छः महीने राष्ट्रपति शासन का मिल जाएगा तो जो कमियां हैं, जो कूड़ा-करकट है, वह साफ हो जाएगा। लेकिन आप चुनाव चाहते हैं तो ठीक है चुनाव में चलिए। आपने पिछले दस सालों में राज्य में सोशल ऑडिट नहीं करवाया है। आपने किसी विभाग का यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजा। आप कहते हैं कि विधान सभा भंग कर दीजिए। विधान सभा को भंग करने की सिफारिश चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री ही कर सकता है। जब झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन वापस ले लिया तो सरकार अल्पमत में आ गयी। बीआरजीएफ की द्वितीय किश्त क्यों नहीं गयी? निशिकांत जी आप पता कर लीजिए, बीआरजीएफ की दूसरी किश्त इसलिए नहीं गयी क्योंकि उसकी यूसी नहीं आयी थी। झारखण्ड आज कृषि में, सिंचाई में, मॉयनोरिटीज़ में, जिस मॉयनोरिटीज़ के साथ पक्षपात होता रहा, पहली बार मायनोरिटीज़ के लिए हमने पैसे की बढ़ोतरी की है। हमने सिंचाई में भी बजट बढ़ाया है। इसी तरह से शिक्षा में भी है। आप इस बात से संतुष्ट होंगे कि जो आपकी सरकार को करना चाहिए था, वह आपकी सरकार ने नहीं किया, आज वह राष्ट्रपति शासन में होने जा रहा है। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि इस पैसे का इस्तेमाल हो जाएगा।

महोदय, इन्होंने बच्चों को टेबलेट बांटने की घोषणा कर दी।...(<u>व्यवधान</u>)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया समाप्त कीजिए। इस बिल को पास करना है। साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिल है।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, मैं एक मिनट में भाषण समाप्त कर दूंगा। 15 नवम्बर, 2012 को इनके मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि झारखण्ड के बच्चों को टेबलट देंगे। नवम्बर में रहे, दिसम्बर में रहे, जनवरी में रहे...(<u>व्यवधान</u>) जनवरी में ही तो राष्ट्रपति शासन लगा।...(<u>व्यवधान</u>) आप ढाई महीने में आप टेबलेट नहीं दे सके।...(<u>व्यवधान</u>) डेढ़ महीने में कैबिनेट में नोट नहीं जा सका।...(<u>व्यवधान</u>) आपमें सरकार चलाने की कोई क्षमता नहीं है।...(<u>व्यवधान</u>) इन्होंने झारखण्ड के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। डेढ़ महीने में कैबिनेट नोट नहीं जा सका।...(<u>व्यवधान</u>) डेढ़ महीने में कैबिनेट डिसीजन नहीं हुआ। ...(<u>व्यवधान</u>) आज तो इनको और इनकी पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए।...(<u>व्यवधान</u>) जबकि हम आकाश के माध्यम से टेबलेट दे रहे हैं। अभी हमने कैबिनेट सैक्रेटरी को भेजा और उन्होंने रांची में मीटिंग की। भारत सरकार के कैबिनेट सैक्रेटरी अपने सभी सैक्रेटरीज़ को ले गए कि झारखण्ड के विभिन्न विभागों में जो पैसा दिया गया है, वह खर्च क्यों नहीं हो रहा है? योजनाएं पूरी क्यों नहीं हुई? उनकी सारी फीडबैक लेकर आए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आप अपना नोट वापस लीजिए और इसको सर्वसम्मति से पास कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष महोदय, झारखण्ड बजट अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं सम्मानित सदस्य निशीकांत दूबे जी और पाल साहब को विस्तार से सुन रहा था। इस बीच मैंने देखा कि पुरानी सरकार की उपलब्धियों का और राष्ट्रपति शासन की उपलब्धियों की चर्चा बडे. विस्तार से पाल साहब ने की। अपने आप में यह बात सही है कि झारखण्ड पूरे देश की शान है। यहां इतनी प्राकृतिक सम्पदा है, कोयला, यूरेनियम, बाक्साइट है। यह पूरे देश की एक तरह से देखा जाए तो धरोहर है। यह भी बात सत्य है कि वहां पूर्व में जितनी भी सरकारें चली हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां मैक्सिमम रही है। अगर चुनी हुई सरकार वहां से हटती है और एक वर्ष में चार-चार गवर्नर बदले जाते हैं तो यह भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी निशिकांत जी कह रहे थे कि 90,000 करोड़ रुपया घटाया गया है। यह गलत बात है। दूसरी तरफ इन की यह भी मांग है कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्ज़ा दिया जाए। पहली बात तो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी किसी भी राज्य के विभाजन के पक्ष में नहीं रही है। अगर किसी परिस्थिति में राज्य का विभाजन हुआ है तो ऐसे राज्यों के उत्थान के लिए, झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के उत्थान के लिए विशेष राज्य का दर्ज़ा देना अति महत्वपूर्ण है। मैं इस की सिफारिश करता हूं।

अभी बड़े विस्तार से बात हो रही थी कि जो हमारे बीपीएल हैं, अति पिछड़े हैं, जिन का जीवन-स्तर बहुत ही निम्न है, वहां भी बजट कम दिया गया है। मेरे ख्याल से बीपीएल का रिव्यू हो रहा है। फिर से बीपीएल की सूची बन रही है। बी.आर.जी.एफ. के बारे में बात हुई। पहले तो इसे राष्ट्रीय सम विकास योजना कहते थे। बी.आर.जी.एफ. में पैसा इसलिए जाता है कि उस जिले का उत्थान हो।

जहां तक हेल्थ की बात की गयी है तो मेरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो आप 108 नंबर पर टेलीफोन कीजिए, मुश्किल से पांच मिनट के अंदर वहां एम्बुलेंस पहुंच जाती है। यह व्यवस्था होनी चाहिए। आज ज्यादातर ऐसे लोगों की मृत्यु हो रही है जिन्हें प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है। जब एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाते हैं तो वे दम तोड़ देते हैं। इन तमाम योजनाओं को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। संविधान में यह है कि सब को शिक्षा, सब को स्वास्थ और सब को रोज़गार मिले लेकिन आज भी देश को आज़ाद हुए पैंसठ वर्ष होने के बावजूद भी हम ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। इन्होंने हॉस्पीटल की बात कही। वहां हॉस्पीटल होने चाहिए। अगर रेशियो देखा जाए तो वहां के बच्चों में कुपोषण, महिलाओं में एनीमिया अर्थात् हेमोग्लोबिन की कमी है। ऐसे अवसरों पर देखना चाहिए कि जो राज्य पिछड़े हैं वहां पर मेडिकल की सुविधाएं हों, एम्बुलेंस हों, तमाम डॉक्टर्स हों। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर के अच्छे-अच्छे निवास हों, नर्सेज हों और दवा की व्यवस्था होनी चाहिए तभी वह राज्य विकास कर सकता है।

एजुकेशन के मामले में मॉडल स्कूल की बात कही जा रही है। केन्द्र सरकार ने 203 मॉडल स्कूल खोलने की बात कही है। ऐसे जो पिछड़े राज्य हैं और खासकर ऐसे जो ब्लॉक्स हैं जहां पर एजुकेशन न के बराबर है, ऐसे जिलों का चयन कर के वहां पर मॉडल स्कूल खोलने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि देश के जितने भी ब्लॉक्स हैं, क्षेत्र पंचायत हैं वहां पर एक-एक मॉडल स्कूल खोलना अति आवश्यक है। यह व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। वहां पर स्कूल भवन नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, यह केवल झारखंड की बात नहीं है बल्कि अन्य राज्यों की भी बात है। अगर हम सर्व शिक्षा अभियान में हर साल बजट बढ़ा रहे हैं तो यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां पर जो बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, जिन के सिर पर छत नहीं है, जो घर से टाट-पट्टी ले कर जाते हैं और उस पर बैठ कर पढ़ते हैं तो

वहां पर टीचर्स और भवन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जहां तक प्राविधिक शिक्षा की बात कही गयी है, जिस क्षेत्र में आई.टी.आई. या पॉलिटेक्नीक नहीं खुले हैं उस क्षेत्र के तमाम युवक रोज़गार से बिल्कुल वंचित हैं। उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं। अभी कल ही जब बजट पर चर्चा हो रही थी तो कौशल विकास के बारे में आप ने कहा कि हम पचास लाख रुपये या साठ लाख रुपये महिलाओं को, नवयुवकों को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं। जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर पॉलिटेक्नीक और आई.टी.आई. की व्यवस्था हो। हमारी जो शिक्षा है वह रोज़गारपरक होनी चाहिए। आप को शिक्षा को रोज़गार से जोड़ना पड़ेगा तभी हम कौशल विकास में आगे बढ़ पाएंगे।

ग्राम विकास में पी.एम.जी.एस.वाई. की बात कही गयी। जो पिछड़े और रिमोट एरिया हैं, अगर वहां पर हमारी सड़कें दुरूस्त नहीं हैं तो वह क्षेत्र कभी विकास नहीं कर सकता। यह बात सही है कि जो राज्य बॉर्डर पर हैं, जो नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े हैं, वहां पर भी कानून-व्यवस्था के नाम पर आप को अलग से बजट देना चाहिए।

पर्यटन में देवघर, पारसनाथ आदि तमाम ऐसे पर्यटन स्थलों की बात आप ने कही है। वहां पर ऐसे संसाधन जुटाने चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, कि वहां टूरिस्ट आए और वहां का राजस्व भी बढ़े।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए।...(व्यवधान) पावर प्लांट होना चाहिए, राज्य अपने ऊपर निर्भर हो सके। दूसरी बात पंचायत के चुनाव की है, जो मेन मुद्दा है। अगर पंचायत के चुनाव नहीं हुए तो मेरे ख्याल से गांव का विकास नहीं होगा, राज्य और देश का विकास भी नहीं हो सकता। इसलिए वहां पर पंचायत के चुनाव कराए जाएं। ...(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य: हो चुके हैं।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: वह तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। निशिकांत जी और तमाम माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दें ताकि वहां का डेवेलपमेंट हो।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही गंभीर मसले पर पिछड़े हुए राज्यों के भविष्य के विषय में संसद में चर्चा हो रही है। जब संसद में किसी मुद्दे पर चर्चा होती है तो सिर्फ देश के ही लोगों की नजर नहीं रहती, बल्कि कुछ मुद्दों पर विदेशों की भी नजर रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब झारखंड बनने की घोषणा हुई, मैं वहां विधान सभा में सदस्य के रूप में मौजूद था। उस समय अखंड बिहार था। सच यही है कि हमारे आदरणीय सांसद इन्दर सिंह नामधारी जी भी उसी विधान सभा के तत्कालीन सदस्य थे। जब विधान सभा में यह घोषणा हुई कि झारखंड का निर्माण हुआ, झारखंड हमसे अलग हुआ, झारखंड के सभी सम्मानित विधायक हमसे अलग हो जाएंगे, तो एक विदाई समारोह का आयोजन हुआ। विधान सभा में जब विदाई समारोह का आयोजन चल रहा था तो वहां का दृश्य काफी मर्मात् था। ऐसी दर्दनाक स्थिति थी, कि उस समय के तत्कालीन विधानसभा के सदस्य इन्दर सिंह नामधारी जी, जो आदरणीय सांसद है, वहां मौजूद थे। मैं यह कह सकता हूं कि इतना दर्दनाक दृश्य था कि कई-कई विधायकों की आंखों से आंसू छलक रहे थे। वहां कुछ लोग अपनी वेदना, व्यथा को सुना रहे थे, कि इस झारखंड के बनने के बाद कोई लाभ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब झारखंड का निर्माण हुआ, जिस समय झारखंड राज्य बना, उस समय हिन्दुस्तान की सर्वोच्च पंचायत में एनडीए की सरकार थी। इसी संसद भवन में एनडीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार ने उस पिछड़े हुए राज्य की काफी मदद की। उनकी मदद से पूरे देश में यह चर्चा होने लगी और मैं तो सट्टे हुए बिहार, झारखंड का सहोदर भाई रहा हूं। मुझे मालूम है कि ऐसी चमक सड़कों पर आई, शासन-प्रशासन में इतना परिवर्तन हुआ, लोगों को लगा कि वास्तव में झारखंड बनाने का जो उद्देश्य था, कि यहां के लोगों की गरीबी, बेबसी, लाचारी, भुखमरी एवं बेरोजगारी मिटेगी। निश्चित तौर पर वहां के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, वह देखने को मिला था।

उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 2004 तक तो विकास की गाड़ी काफी तेजी से चली। जब हम लोग विधायक बन करके बिहार की सड़कों से गुजर करके सामने झारखंड के दरवाजें पर पहुंचते थे, जहां एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि झारखंड आपका स्वागत करता है। उन सड़कों पर चलने में नींद आ जाती थी। जब कहीं दूसरे राज्यों से झारखंड होकर निकलते थे, झारखंड की सीमा जहां प्रारम्भ होती थी, अंत तक आरामदायक लगता था। लेकिन जैसे ही दूसरे राज्यों में प्रवेश करते थे, नींद टूट जाती थी, बिहार में हिचकोले मारने लगती थी। लेकिन 2005 में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, पैसे काट लिए गए। गरीबी, बेबसी और लाचारी की जो सीमाएं थीं, उन सीमाओं में कोई कटौती एवं कमी नहीं आई। वहां के करोड़ों नौजवान, जिनके हाथों में ताकत है, अपनी बूढ़ी मां को छोड़कर, बूढ़े बाप को छोड़कर जवान पत्नी छोड़कर, छोटे-छोटे अबोध बच्चों को छोड़कर वे वहां से पलायन कर गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री भूदेव चौधरी : मैं उनका दर्द सुना रहा हूं, मैं अपनी व्यथा सुना रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति आपको मालूम है, 2005 में यू.पी.ए. की सरकार थी, फिर 2008 में यू.पी.ए. की सरकार थी और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। फिर 2010 में और फिर 2013 में, 12 साल के क्रम में लगभग 8 बार मुख्यमंत्री बदले गये, 8 बार वहां के राज्यपाल बदले गये,

'जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,

वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।'

झारखण्ड ने जंगे आजादी में अपनी अहम भूमिका अदा की, झारखण्ड के बिरसा मुण्डा को कौन नहीं जानता, जो देश का एक ऐतिहासिक पुरुष रहा है, कौन नहीं

जानता तिलका मांझी को, जिन्होंने अपने तीर कमान से अंग्रेजों के सिपाहियों को खदेड़ दिया, कौन नहीं जानता सिद्धू खांडू को, जिन्होंने लड़ते-लड़ते अपनी जिंदगी गंवा दी, अपनी जवानी गंवा दी, लेकिन प्रयास जारी रहा और झारखण्ड बन गया, लेकिन आज भी मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि वहां की गरीबी, बेबसी और लाचारी में कोई कमी नहीं आई है।

आज भी वहां के 70 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। पैदा होते ही वे बीमारी के गर्त में चले जाते हैं, विकलांग पैदा होते हैं, कितनी ही मां-बहनों का तो गर्भपात हो जाता है, वहां आज भी 70-80 प्रतिशत महिलाओं के शरीर में खून नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा होते हैं तो कम उम्र के पैदा होते हैं। जंगल और जमीन, इसके अलावा तो झारखण्ड में कुछ है नहीं, लेकिन मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद देश को बनाने में आधी ताकत झारखण्ड और बिहार की लगी है। इस देश में सबसे ज्यादा खनिज सम्पदा, कोयले की खदान, लोहे का पहाड़, अभ्रक की भरमार है। झारखण्ड और बिहार की धरती से दूसरे राज्य विकसित हो गये हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि आजादी के बाद देश में विकास नहीं हुआ, विकास तो हुआ, लेकिन जिस भारतीय जंगे आजादी में वहां के लोगों ने अपनी जवानी दे दी, कुर्बानी दे दी, उस बिहार और झारखण्ड की उपेक्षा होती रही, इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए यह आग्रह करता हूं, वहां की जनता की जिज्ञासा, इच्छा और अपेक्षा है, मैं अपने स्तर से प्रतिनिधि चुनाव करूं। आज बहुत दुख और भारी मन के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस बजट की चर्चा राज्य की विधान सभा में होनी चाहिए, वह चर्चा यहां हो रही है, यह मेरा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं आज यह विनती करना चाहता हूं, आपके माध्यम से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि लोकतंत्र जिंदा तब रहेगा, जब जनता के माध्यम से चुन कर सरकार बनेगी, इसलिए मेरी अपील है और मेरी गुज़ारिश है कि वहां राष्ट्रपति शासन को हटायें, राष्ट्रपति शासन को हटा करके वहां लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव करायें। वहां विधान सभा फिर से शुरू हो और लोगों की इच्छा और आकांक्षा पूरी हो सके, वरना मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं::

'छेड़ने से मूक भी वाचाल हो जाता है, टूटने पर शीशा भी काल हो जाता है,

इस तरह गरीब राज्य को मत सताओ, वरना जलने से कोयला भी लाल हो जाता है।'

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पुलीन बिहारी बासके (झाड़ग्राम): उपाध्यक्ष जी, मुझे आपने बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं और मेरा जो क्षेत्र है, वह झाड़ग्राम पार्लियामेंटरी कांस्टीट्वेंसी है। उसके साथ झारखण्ड प्रदेश है, वह पड़ौसी प्रदेश है, मेरे क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज झारखण्ड बजट के बारे में जो चर्चा हो रही है, उसके पहले तो जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रपति शासन शुरू हुआ है। उसकी जब चर्चा हो रही थी तो उसमें हम भाग नहीं ले सके। हम तो राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हैं। राÂष्ट्रपति शासन लोकतंत्र के खिलाफ है, इसलिए मैं भी राष्ट्रपति शासन का वहां विरोध करता हूं और यह भी मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी वहां चुनाव का प्रोसैस शुरू किया जाये, ताकि चुनी हुई सरकार झारखण्ड राज्य को संभाल सके, वहां राज कर सके और बजट पर भी वहां चर्चा हो सके।

लेकिन मेरा कहना है कि झारखण्ड स्टेट जैसा लग रहा है कि वहां पैराडॉक्सीकल सिचुएशन है। एक तरफ खनिज सम्पदा जो है, आयरन ओर है, कोयला है, और भी मिनरल्स ज्यादातर वहां पर हैं और दूसरी तरफ ह्यूमन रिसोर्स डैवलपमेंट आप देखिएगा, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादातर वहां है और भुखमरी भी है और बेरोजगारी भी है। ऐसी हालत है और उस स्टेट में ज्यादातर आदिवासी लोग, करीब 70 लाख से अधिक आदिवासी लोग रहते हैं। वे वहां करीब 25 परसेंट हैं और आदिवासी लोगों के लिए पीने का पानी भी नहीं है, जाने का रास्ता भी नहीं है, रहने को मकान भी नहीं है तो वे लोग कहां जाएंगे। इसीलिए तो नक्सलवाद पैदा हो जाता है, फैल जाता है और इसी को हमें भुगतना पड़ रहा है कि पिछले दो-तीन वर्षों में देखा है कि नक्सलवाद बंगाल में भी फैला हुआ है, पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट मेरा जो क्षेत्र है, बांकुरा है, पुरुलिया है, करीब 500 लोगों की नक्सलियों ने, माओवादियों ने वहां हत्या कर दी है और उनमें ज्यादा से ज्यादा आदिवासी लोग हैं। झारखण्ड स्टेट में भी करीब 19 डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां झारखण्ड राज्य में माओवादी फैल गये हैं। इधर हम देखते हैं कि 65 हजार जो लोग हैं, वहां से उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि, जमीन से उन लोगों को हटा दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय यहां हैं, आप जानते होंगे कि माइनिंग प्रोजैक्ट के लिए जो सारन्दा प्रोजैक्ट है, उसमें कितना फोरैस्ट लैंड डाइवर्ट हो गयी है, 88.650 हैक्टेयर लैंड डाइवर्ट हो गई है। जिन्दल स्टील एण्ड पावर प्रोजैक्ट के लिए 500 हैक्टेयर लैंड और सेल के लिए 210, कुल मिलाकर के 799 हैक्टेयर फोरैस्ट लैंड को डाइवर्ट किया गया।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री पुलीन बिहारी बासके : उन आदिवासी लोगों को हटा दिया गया है, बिना कोई मुआवजा दिये और वहां की जो सिचुएशन है, जो हमारे यहां बहुत सारी नदियां हैं, छोटा नागपुर से आती हैं, चण्डेल डैम है और बहुत सारे डैम है, बारिश के समय बाढ़ आती है, इससे हमको फायदा मिलेगा, क्योंकि, सूखे इलाके को फायदा मिलेगा, इसलिए यह भी देखना पड़ेगा। जो फोरैस्ट एक्ट का कानून है, वह भी प्राथमिकता से लागू हो, यह भी देखना है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पुलीन बिहारी बासके : बहुत सारी बातें बोलने के लिए हैं, लेकिन मैं यह मांग करता हूं कि जो यह टीका-टिप्पणी हो रही है, चाहे एन.डी.ए. के भी जो लोग हैं और इधर के भी लोग हैं, वहां जो घोटाला है,

सबसे ज्यादा करप्शन वहां हो रहा है। मनरेगा के बारे में और ग्रामीण विकास के बारे में भी बहुत बात हुयी है। यहां करप्शन बंद किया जाए। आज जिस तरह से यहां बहस हो रही है, हम कहना चाहते हैं कि झारखंड नया-नया स्टेट बना है, वहां करीब आठ मुख्यमंत्री हुए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री पुलीन बिहारी बासके: वहां करप्शन को खत्म किया जाए। जहां तक झारखंड के विकास का सवाल है, इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। मैं इसके लिए मांग करते हुए और आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I stand here today to speak on the State Budget of Jharkhand. Shri Nishikant Dubey ji has elaborately dealt with the issues relating to Jharkhand. The day the Bill was moved to create Jharkhand State on 14th November, 2000, I was a witness to that in this House. At that time, from our Party, a senior Member had commented that Odisha was created out of Bihar-Odisha province on 1st of April, 1937. At that time, we were very happy. Subsequently, it led to the formation of the province of Odisha in 1948 with the amalgamation of all princely States. Yet, two princely States went back to Bihar. At that time, one of our senior Members on 14 th November, 2000 had said that it was in 14th November, 1948 that the first princely State was annexed to Indian Union. That was called Nilgiri. Again on 14th November, providence has played a role that those two princely States which were taken forcibly to Bihar in 1948 has again been bifurcated from Bihar. So, while hearing Shri Bhudeo Choudhary today about what had occurred on that day, I still recollect that speech of Shri Kanungo who had narrated that incident.

I would delve into only two issues here. One is the formation of small States. Is it beneficial for our country or not? The Bhartiya Janata Party is of the opinion that more the smaller States are created, it is better for the nation. I am of the opinion that in some aspects, creation of smaller States has brought in development of our nation. But not in political sphere, it has not created that much of stability in those regions. The first State that was bifurcated was Punjab. Later on, Assam was divided into a number of States. That was also in the sixties when Shrimati Indira Gandhi was the Prime Minister. Subsequently, during Shri Atal Behari Vajpayee's time, three new States were formed. That shows us that if Uttarkhand can prosper, if Himachal Pradesh can prosper, why is Jharkhand in so much of political turmoil? The issue here is that it is in political turmoil because there is a fractured mandate always that is being reflected in different elections. Despite that, the two major national parties who are entrenched in Jharkhand, still

it is getting fractured mandate. Why is it so? Why is it happening? This is an issue which I think, all political parties should delve into and try to find out a solution.

We know that unless you have a stable political leadership in Jharkhand, if established leadership is proved in Jharkhand, then only we can get better results, better administrative set up. Whatever has been discussed till now, it will be wise to have that investment for development of Jharkhand. That is not happening. And our Party, the Biju Janata Dal has always been opposed to imposition of the President's Rule in any part of the country.

15.00 hrs.

Odisha has been a victim of that. Odisha had been a victim for three decades, 30 years, of fractured mandate. Subsequently, since 1980 Odisha progressed to get a stable mandate and for the last 30 years, we have a stable Government, be it of Congress or Biju Janata Dal or Janata Dal.

I think progress will be made but all the respective political parties have to live up to that situation and create a public opinion that for stability of Jharkhand, for progress of Jharkhand, we need a better mandate so that stable Government can be formed.

The Minister for Finance has assured us in this House that the intention of the UPA Government is not to continue it till the end of six months. Elections may take place in between but my only request to both the Bhartiya Janata Party and to the Indian National Congress is to create a political situation where you do not get a fractured mandate so that stable government can be formed.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कामेश्वर बैठा, कृपया संक्षेप में मुख्य-मुख्य बिन्दु पर बोलिए क्योंकि समय थोड़ा कम है।

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): महोदय, मैं झारखंड का हूं और यह झारखंड का बजट है तो संक्षेप में क्यों बोलवा रहे हैं। इसके लिए कम से कम दस मिनट का समय दिया जाए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : समय कम है। आप शुरु कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह समय झारखंड का नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

श्री कामेश्वर बैठा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे झारखंड के बजट पर बोलने का मौका दिया है इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं पहले वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बजटीय भाषण में स्वीकार किया है कि झारखंड राज्य में जंगल है। यह खनिज-संपदा से भरा हुआ है। फिर भी, झारखंड आज गरीब है। इसके लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे झारखंड को देखा और समझा है। मैं जयराम रमेश जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने मंत्री काल में अनेकों बार झारखंड का दौरा किया है और बड़े से बड़े हिस्से में घूम कर हमारे झारखंड के लोगों को देखा है। उसका एक प्रतिफल है कि उन्होंने हमारे झारखंड पलामू संसदीय क्षेत्र भंडरिया में जाकर साढ़े चार हजार इंदिरा आवास का आवंटन किया था। मैं कहना चाहता हूं कि बजट भाषण में जो पेश किया गया है वह झारखंड के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी मैंने निशिकांत दुबे जी का भाषण सुना, पाल जी का भाषण सुना, अभी कई और लोग भाषण देंगे। हम समझते हैं कि जब से झारखंड राज्य बना है तब से झारखंड राज्य आज भी वहीं पर है, जहां कल था। इसका कारण क्या है? हम समझते हैं कि इसका दो कारण है। झारखंड को स्वतंत्र अधिकार अधिकार का, स्वतंत्र निर्णय करने का कभी मौका नहीं दिया गया। अभी 18-18 महीने का समझौता सब लोग देख रहे हैं लेकिन कोई यह नहीं कह रहा है कि झारखंड मुक्ति मोरचा, बीजेपी से समर्थन लिया तो क्या मात्र 18 महीने का है, नही। झारखंड की मूल समस्या, झारखंड में जो बीजेपी और जेएमएम दोनों के गठबंधन से जो सरकार चल रही थी उसमें हमारी कुछ शर्त थीं। निशिकांत दुबे जी को इस बात को बोल देना चाहिए कि वे शर्तें क्या थीं? वे आठ प्वाइंट्स थे। मैं झारखंड का विकास चाह रहा था। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बजट पर बोलिए।

श्री कामेश्वर बैठा : मैं दो बातें बोलना चाह रहा हूं। आज तक झारखंड का विकास नहीं हुआ है।

हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आपने जो बजट पेश किया है चाहे वह सिंचाई के सवाल पर, रोड के सवाल पर, स्वास्थ के सवाल पर, मैं अपने पलामू संसदीय क्षेत्र के बारे में वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। आज हमारे पलामू संसदीय क्षेत्र के हालात क्या हैं, वहां की दीन-दशा कैसी है। हम समझते हैं कि यही दीन-दशा झारखंड के बड़े हिस्से में है। अगर आपने कुछ पैसा दिया भी है तो मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं होगा। मैं जेएमएम का सांसद जरूर हूं, लेकिन बजट में जितना पैसा गया, उस समय जो मंत्री रहे, चाहे * आदि सब अपने-अपने क्षेत्र में पैसे ले गए, पूरे झारखंड में पैसे वितरित नहीं किए गए। अगर आज देखेंगे तो रोड ... * के क्षेत्र में बनी है, ... * के क्षेत्र में बनी है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं, कृपया उनका नाम नहीं लिया जाए।

â€¦(व्यवधान)

श्री कामेश्वर बैठा : महोदय, मुझे बोलने दिया जाए। हमें झारखंड के बारे में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। मैं पलामू का सांसद हूं। मुझे कम से कम पलामू संसदीय क्षेत्र के इतिहास के बारे में बताने दीजिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री कामेश्वर बैठा: हमारा संसदीय क्षेत्र जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। पलामू संसदीय क्षेत्र में नक्सलवाद है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी, श्री जयराम को कहना चाहता हूं कि झारखंड खासकर जो अति पिछड़ा क्षेत्र था, अति उग्रवाद क्षेत्र था, वहां एक आईआईटीएफ योजना चलाई गई थी। वह योजना बंद हो गई।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री कामेश्वर बैठा : कैसे समाप्त कर दें। हमें बोलने दिया जाए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को अपनी बात लिखकर दे दीजिए और समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री कामेश्वर बैठा: अपनी बात समाप्त करके मैं बैठूंगा। ...(व्यवधान)

---

* Not recorded

उपाध्यक्ष महोदय, समय निर्धारित किया गया है। मैं झारखंड का सांसद हूं। मुझे वहां के बजट के बारे में बोलना है और आप कह रहे हैं कि समाप्त

कीजिए।...(व्यवधान) हमें बोलने दिया जाए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप नाम मत लीजिए। श्री नामधारी जी, आप बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री कामेश्वर बैठा: आपने मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई परियोजना के लिए ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए और समाप्त कीजिए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2013-14 का झारखंड बजट प्रस्तुत किया है। मैं इनके बजट भाषण को पढ़ रहा था। मैं कुछ बिंदुओं पर सहमत हूं और कुछ बिंदुओं पर सहमत नहीं हूं।

> "It is with deep regret that I am constrained to say that the promises made twelve years ago remained unfulfilled."

I agree. आपने यह ठीक कहा कि बारह सालों के बाद भी वहां के लोगों की जन-आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई।

> "Hon. Members are aware of the recurrent political instability, governance deficit and collapse of institutions that plagued the State in the previous two stints of President's rule. We tried, in whatever little time we got, to bring some order in a chaotic situation. "

I differ. Very humbly I want to say that I differ with this. ...(*Interruptions*) I will complete it. He has further stated:

> "And put the State back on the path of development, we have achieved only limited success."

Why have you achieved only limited success? It is because there were some flaws in the President's rule also. I do not want to name the Governors who indulged in foul play.

एक पतंगे की क्या इतनी हिम्मत कि खुद-ब-खुद आग में कूद जाए

हाथ है कुछ क्षमा का भी इसमें, खुद से परवाना जलता नहीं।

राष्ट्रपति शासन केवल एक बार नहीं हुआ, चार बार हुआ। राष्ट्रपति शासन में कैसे-कैसे काम किए गए, मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं। कम से कम उसकी पुनरावृति न हो। मुझे शंका है कि उसकी पुनरावृति होगी। लेकिन आपने हाउस को आश्वस्त किया है कि हम जल्दी से जल्दी वहां पर चुनाव करवाना चाहते हैं। आपके इस कथन पर मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि हमने वे सीन देखे हैं। वर्ष 2009 में चुनाव के समय वहां पर राष्ट्रपति शासन था और राष्ट्रपति शासन में ऐसा सिद्ध किया गया कि चुनाव जीतने के लिए जो कुछ करना है, कर दो। वहां फ्री अनाज बांटा गया। यशवंत सिन्हा जी इसके गवाह होंगे। हजारीबाग और हमारे क्षेत्र चतरा में लाठीचार्ज हुए। ...(व्यवधान) राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति का शासन होता है। अगर कोई समझे कि यह एक पार्टी का शासन है, तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति, जो संवैधानिक मुखिया होता है, उसका भी आप अपमान कर रहे हैं। वहां फ्री अनाज बांटकर लोगों को आपस में लड़वाया गया क्योंकि बीपीएल की सूची डिफेक्टिव थी। जो गरीब थे, उनको अनाज नहीं मिला और जो धनी थे, वे अनाज लेकर चले गये। जगह -जगह पर लाठीचार्ज हुए। सैंकड़ों-हजारों लोग जेलों में चले गये। यह भी राष्ट्रपति शासन में हुआ। मैं जयराम रमेश जी की बहुत कद्र करता हूं, सम्मान करता हूं। ये झारखंड का खास ध्यान रखते हैं, लेकिन वहां थोड़ा सा दुरुपयोग हो रहा है, यह मैं आपके कानों में डालना चाहता हूं।

आपने साढ़े चार हजार इंदिरा आवास दिये, यह बड़ी अच्छी बात थी। भंडरिया एक ऐसा प्रखंड है, जहां का मैं छः बार विधायक रहा हूं। वह गढ़वा जिले में पड़ता है, लेकिन डाल्टेनगंज का पार्ट है। साढ़े चार हजार, अभी कामेश्वर बैठा जी ने भी कहा, लेकिन साढ़े चार हजार आवास बांटते समय वहां क्या ड्रामा हुआ? वहां के सांसद को सूचना नहीं दी गयी और जो निलंबित विधान सभा है, उसके विधायक के हाथों से यह कहकर दिया गया कि मैं पैसा लाया हूं, मैं इंदिरा आवास लाया हूं। जयराम रमेश जी, यह कौन सा सीन क्रिएट कर रहे हैं? ...(व्यवधान) यह मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं उसे आपके कान में डाल दूं। आपकी मंशा शुद्ध हो सकती है। आप झारखंड के लिए यज्ञ कर रहे होंगे, लेकिन इस यज्ञ से लोगों के हाथ जल रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप संक्षेप में बोलिए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: मैं एकदम संक्षेप मे बोलूंगा। मैंने वित्त मंत्री जी के भाषण को पढ़ा है। उसे पढ़कर मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं कि

> "â€¦.to put the State back on the path of development.
> We achieved only limited success."

Why was there a limited success? I am trying to describe it. इसलिए अगर आप जल्दी चुनाव करवा दें, तो अच्छा है, क्योंकि दो महीने का टाइम कम नहीं होता। वहां कोई पार्टी आकर क्लेम नहीं कर रही है कि हमें सरकार बनाने दीजिए। लेकिन जब कोई पार्टी क्लेम नहीं कर रही है, तो क्या आप इंतजार करते रहेंगे कि आओ। इसका मतलब यह लगेगा कि आप इनडायरेक्टली रिमोट कंट्रोल से वहां पर शासन करना चाहते हैं, क्योंकि 12 सालों में कांग्रेस को वहां शासन करने का मौका नहीं मिला। इसलिए राष्ट्रपति शासन को आप कांग्रेस का शासन बनाना चाहते हैं। अगर इस तरह से निलंबित विधान सभा के विधायक एक-एक व्यक्ति के पास बैठकर चार-चार हजार इंदिरा आवास बांटेंगे ...(व्यवधान) मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ। डीसी और वहां के जो अफसर थे, वे वहां गये। उन्होंने केवल काम शुरू किया, एक-दो आवास बांटे ...(व्यवधान) फिर उसे निलंबित विधायक पर छोड़कर चले गये। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: मेरा कहना है कि अगर सिटिंग एमपी हैं, तो क्या उनका हक नहीं है कि वह उस कार्यक्रम में जायें। ...(व्यवधान) Why are they not invited? ...(*Interruptions*)

श्री यशवंत सिन्हा: आप यह बताइये कि हम जो सांसद हैं, उन सबको एक बार भी राज्यपाल महोदय ने निमंत्रण दिया कि आइये, हम झारखंड के बारे में आपसे विचार-विमर्श करना चाहते हैं। क्यों नहीं वे झारखंड के सारे सांसदों को बुलाते? जो मंत्री हैं, वे उन्हें क्यों नहीं बुलाते? आप उन्हें बुलाइये। ...(व्यवधान)

श्री जयराम रमेश: मैं रोज उनसे मिलता रहता हूं। झारखंड के सांसदों से रोज मिलता हूं। ...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा: रोज मिलते हैं, इंडीविजुअली मिलते हैं। आप सबको एक साथ बुलाइये। एक बार आपने बुलाया था, लेकिन उसके बाद नहीं बुलाया। ...(व्यवधान)

श्री इन्दर सिंह नामधारी: उपाध्यक्ष महोदय, दिल में â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, तो मैं इनके चैम्बर में गया था। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इसे आज पास भी करना है इसलिए आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि झारखंड की कैसे उपेक्षा होती है? मैं इनके चैम्बर में गया और कहा कि पिछले दो दशकों में हमने जितने नजदीक से उग्रवाद को देखा है, उतना शायद कोई अफसर आपको नहीं बता सकेगा, कोई डीजीपी नहीं बता सकेगा। जो मैं आपको बताता हूं। एक रोड है, मनातू में, जो पलामू जिला में पड़ता है और प्रताप पुर, जो चतरा जिला में पड़ता है, यदि इसे जोड़ दें, तो चार जिलों में 50 प्रतिशत उग्रवाद समाप्त हो जाएगा। उन्होंने मुझे लिखित रूप में आश्वासन दिया कि I am including it in the RRP – Phase II. लेकिन इनके लिखित आश्वासन के बाद भी आज तक वह सड़क पास नहीं हुई। यदि वह सड़क बन जाती, मैंने चिदम्बरम साहब से यह भी आग्रह किया था कि आप उस सड़क को बीआरओ से बनवा दें। उन्होंने कहा कि How? I will give money to the State. इस पर मैंने कहा कि स्टेट को देने के बाद भी वह सड़क बन नहीं पाएगी। आज संयोग से चिदम्बरम साहब और जयराम जी दोनों यहां बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बोल दिया, उन्होंने लिख लिया है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी: एक तो मैं इंडिपेंडेंट मेम्बर हूँ, वैसे ही कम बोलता हूँ। मैं समय भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि आप सबसे अंतिम में दो मिनट का समय देंगे।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं चिदम्बरम साहब को कि राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति शासन रहने दीजिए। इस तरह से यदि नेकेड काम किये गये, तो मुझे शक है कि चिदम्बरम साहब ने जो कहा कि we achieved only a limited success. इससे भी कम लिमिटेड सक्सेस आपको राष्ट्रपति शासन में मिलेगी, यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): सभापति महोदय, मैं चिदम्बरम साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे झारखण्ड में जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। जब निशिकांत जी बोल रहे थे, तो मुझे हंसने वाली बात लग रही थी क्योंकि झारखण्ड में सबसे ज्यादा समय तक बीजेपी की सरकार रही है। वहां जितनी भी विफलताएं हुई हैं, उसमें वे लोग किसी भी तरह से उस सरकार में शामिल थे। पिछले साल 15 नवम्बर की बात है, एक विज्ञापन में निकला था, जिसमें वर्तमान झारखण्ड सरकार के मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री का फोटो छपा था। यदि उस विज्ञापन को देखें, तो उसमें लिखा है कि "विकास के पथ पर अग्रसर झारखण्ड, जमीन पर उठी हकीकत।" इससे बड़ा *â€¦ **

कहीं नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस असंसदीय शब्द को निकाल दिया जाए।

श्री अजय कुमार : इससे ज्यादा गलत बात नहीं हो सकती है। झारखण्ड की जो स्थिति है, वहां पर 80 प्रतिशत बच्चे और महिलाएं एनिमिक हैं। यदि आप देखें, तो 65 लाख लोग झारखण्ड से विस्थापित हुए। जहां तक हमारे दोस्तों का कहना है कि जितने ज्यादा एमओयू साइन हुए थे, सबसे ज्यादा एमओयू *â€¦**की सरकार में साइन हुए। जिनमें गरीब आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने की उन्होंने पूरी कार्रवाई की। इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन एक बात जरूरी याद दिलाना चाहूँगा कि 57 कोयला ब्लॉकों में से 27 कोयला ब्लॉकों का आवंटन *â€¦** ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को आवंटित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी का नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्री अजय कुमार: एक सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों ने पेंशन के बारे में की थी। मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध होगा कि पेंशन का जो भार झारखण्ड पर पड़ा है, उसे पापुलेशन के आधार पर किया जाए। क्योंकि स्टेट का जब रिआर्गनाइजेशन हुआ था, तो स्टेट के पापुलेशन को आधार मानकर किया गया था और सिर्फ झारखण्ड में सरकारी पदाधिकारियों की संख्या लेकर किया गया था। आपसे अनुरोध है कि उसमें संशोधन किया जाए।

---

*Not recorded

15.19 hrs. (Shrimati Sumitra Mahajan *in the Chair*)

झारखण्ड की स्थिति के बारे में जितना बोलूंगा, उतना ही कम होगा। आपसे अनुरोध होगा, वित्त मंत्री जी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जयराम रमेश जी तो चले गए, लेकिन एक चीज जरूर है, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राईस को आदिवासी लोगों के लिए ध्यान दिया जाए। वित्त मंत्री महोदय ने केवल महिलाओं के लिए एक स्पेशल बैंक के गठन की बात कही थी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आदिवासी लोगों की प्रोन्नेस के लिए एक बैंक का गठन करने की आवश्यकता बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पैसे की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। झारखण्ड में न कोई एम्स है, न कोई आईआईटी है।

हम लोग बार-बार कहते हैं कि हम पिछड़े क्षेत्रों का ध्यान रखना चाहते हैं, लेकिन यह अफसोसजनक बात है कि हमारे पास सिर्फ 20 वोकेशनल हायर सेकण्डरी इंस्टीट्यूट्स हैं जबकि आंध्र प्रदेश में 560 हैं, केरल में 500 हैं। इससे स्पष्ट होता है कि झारखण्ड को किस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। जहां तक सर्वशिक्षा अभियान की बात है, कुछ पूर्वी गरीब राज्यों के लिए समस्या है। आप सर्वशिक्षा अभियान में 50-50 प्रतिशत समर्थन देते हैं। आप देखते हैं कि झारखण्ड में किसी भी स्कूल में टीचर्स नहीं हैं। मैं वित्तमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पिछड़े हुए राज्य को भारत सरकार 75 प्रतिशत योगदान दे और 25 प्रतिशत राज्य सरकार दे। अभी तक सर्वशिक्षा अभियान में कभी झारखण्ड सरकार ने 50 प्रतिशत राशि देने का कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाई है। बहुत से माननीय सदस्यों ने अनेक बातें कही हैं, लेकिन मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि झारखण्ड एक ऐसा राज्य है जिसके लिए स्पेशल स्टेटस अनिवार्य है। पूरे देश में यही ऐसा प्रदेश है जहां 20 प्रतिशत लोग गांवों में कच्चे मकानों में रहते हैं और 70 प्रतिशत लोग शहर में कच्चे मकान में रहते हैं। अन्य किसी प्रदेश में इतनी खराब स्थिति नहीं है। अगर किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस की आवश्यकता है, तो वह झारखण्ड है। फाइनली, 75 लाख लोगों का विस्थापन होना आजाद भारत में सबसे ज्यादा दर्दनाक कहानी है। इसलिए मैं वित्तमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कहीं न कहीं से, कम से कम 15000-20000 करोड़ रूपये विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए देने के बारे में सरकार सोचे, नहीं तो यह अनर्थ झारखण्ड की जनता के साथ चलता ही जाएगा।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam, I am grateful to the 9 hon. Members, beginning with Shri Nishikant Dubey and ending with Shri Ajay Kumar, for participating in this debate.

As I said in my speech - which I did not read, but I laid on the Table of the House - Jharkhand was a State that held out great promise. It is a very rich State, but it has, perhaps, the largest proportion of poor people and, perhaps, the worst kinds of governance ever seen in India. There is no shame in admitting that. There were two spells of President's Rule. As I said, we tried our best. But I am not claiming that we had great success. In fact, I visited Ranchi and some parts of Jharkhand several times during that period. But I found that all the institutions had virtually collapsed. One had to build from the grassroots. That was not possible in President's Rule. It can only be built by a democratically elected Government that is devoted to the welfare of the people with the full cooperation of the MLAs and the MPs.

Today we have presented a Budget. In 2009-10 also, when the President's Rule was there, we presented a Budget for the full year. But I will be the happiest person if an elected Legislature, after the Government is formed, amends this Budget. That is the right thing to do. But I am doing the best under the circumstances. I have had discussions with the senior officers as well as the Advisor. I have had talks with the other Advisor who deals with police and security matters. Both of them are fine officers. They will do their best to tone up the administration until elections are held.

I was rather surprised by the extraordinary effort Shri Nishikant Dubey made to defend the Governments and to defend his party. I suppose it is his *dharma* to defend his party. But I think all the King's horses and all the King's men cannot put humpty-dumpty together again.

Madam, I found to my great dismay that Jharkhand did not even have the practice of doing the Revised Estimates. The Budget Estimates will be the Revised Estimates. That was the kind of accounting culture that had come in Jharkhand. Anyway, I have tried to correct them in the limited time available to me with the help of the Advisor.

I do not wish to make a long speech. There was a question about the AIBP. For example, under the Swarnarekha Multi Purpose Project, the funds released in 2011-12 were Rs. 335 crore. In 2012-13, we have not received any request from the Government of Jharkhand for release of funds. Whose fault is this?

SHRI NISHIKANT DUBEY: No.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, I am telling them. They should not say no to everything that we say from this side. In 2012-13, we have received no request for release of funds.

Nevertheless, the Advisor has been told, money has been allocated. Today, we have released Rs. 309 crore as Central Assistance by the Budget Division. The Jharkhand Budget and Plan have never been fulfilled because they cannot raise their own resources nor can they utilize the resources that are devolved upon them by the Central Government. I do not wish to go into the numbers. All I can say is that I sincerely hope this spell of Governor's Rule is a short Rule.

My colleague, Shri Jairam Ramesh, has just had a word with Shri Yashwant Sinha. All the MPs from Jharkhand are invited to a meeting in Ranchi on the afternoon of 23rd March 2013 to advise the Government of India of how to proceed over the next few weeks or months until the election is held. The Governor will be invited, the Advisor will be invited and the meeting can take place as long as it wishes to, maybe two hours, three hours or four hours. I would request them to give their advice and we will try to run the Government in accordance with the advice of the Members of Parliament elected from Jharkhand.

With these words, Madam, I commend the Budget and wish that it is passed.

MADAM CHAIRMAN : I shall now put the Demands for Grants (Jharkhand) for 2013-2014 to the vote of the House.

The question is:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account, shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 2014, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 4, 6 to 12, 15 to 27, 29 to 33 and 35 to 60."

The motion was adopted.

MADAM CHAIRMAN: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (Jharkhand) for 2012-2013 to the vote of the House.

The question is:

> "That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account, shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand, to defray the charges during the year ending the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3, 10, 16, 18 to 20, 22, 23, 25, 26, 33, 36, 40, 41, 43 to 45, 48 to 51, 53, 54, 56 and 58."

The motion was adopted.